Programme Framed for Employment of SC|ST and other Weaker Sections

6061. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have recently framed any programmes with employment potential for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections of the community;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) the time by when these programmes are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (c). The Sixth Five Year Plan document which covers all sectoral programmes, lays considerable emphasis on reducing un-employment particularly for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections. While details of the programmes and schemes are available in the Plan documents including the Special Component Plan and Tribal Sub Plans, some of the programmes which have a large employment potential for these groups include the Integrated Rural Development Programme; schemes in the Animal Husbandry, fisheries, and Agro-Forestry sectors; Operation Flood II; District Industries Centres; programmes of organisations like State Leather Corporations, Handloom Development Corporation Handicrafts Boards, KVIC, Forest Development Corporation etc. These programmes and schemes will continue to be implemented over the Plan periods.

खादी ग्रामोद्योग आयोग में लाभ और हानि

6062. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों में खादी ग्रामोद्योग की अलग अलग कितना लाभ हुआ और इसके कर्मचारियों को वार्षिक बोनस के तौर पर कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ; और

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग को पिछले दो सालों के दौरान, चोरी, गबन इत्यादि के कारण कितना घाटा हुआ ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) संक्षेप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग की योजना बनना और उन्हें संगठित करना ताकि सरकार द्वारा दी गई निधि से ग्रामीण कारीगरों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार मिले और वे जीवकोपार्जन कर सकें । यह उद्योग मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कार्य करता है । जिसके अंतर्गत लगभग 800 संस्थाएं एवं 29,000 सहकारी समितियां हैं । इस प्रकार आयोग एक लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है । आयोग के कर्मचारियों को वार्षिक बोनस नहीं दिया जाता है ।

(ख) 1979-80 तथा 1980-81 की अवधि में आयोग को क्रमश: कर्मियों, चोरियों व आग लगने आदि के कारण लगभग 82,226,99 तथा 7,591,81 रुपये मूल्य के काण माल का नुकसान उठाना पड़ा ।

Survey of Bonded Labour in Agriculture Sector

6063. SHRI H. N. NANJE GOWDA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have made any surety to find out the existence of bonded labour in the agriculture sector in the country;